

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक-२० सितम्बर, 2011

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार शहर की वाटर सप्लाई रिआर्गनाईजेशन स्कीम हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा०स०-२२/IV-श०वि०-०८-०६(एन०यू०आर०एम०) / 08 दिनांक 29-3-2008, शासनादेश संख्या 1646/IV(2)-श०वि०-०८-०६(एन०यू०आर०एम०) / 08 दिनांक 30-12-2008, शासनादेश संख्या 730/IV(2)-श०वि०-०९-०६(एन०यू०आर०एम०) / 08 दिनांक 29-07-2009 एवं शासनादेश संख्या भा०स०/IV(2)-श०वि०-१०-०६(एन०यू०आर०एम०) / 08 दिनांक 31-03-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार शहर की वाटर सप्लाई रिआर्गनाईजेशन की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी०पी०आर० ₹ 4784.43 लाख के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित कुल ₹ 3588.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/PFI/2011-444 दिनांक 27-7-2011 द्वारा उपरोक्त परियोजना हेतु अन्तिम किस्त ₹ 574.13 लाख की अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश ₹ 574.13 लाख के सापेक्ष देय राज्यांश ₹ 143.53 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि ₹ 717.66 लाख (₹ सात करोड़ सतरह लाख छियासठ

हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹ 717.66 लाख (₹ सात करोड़ सतरह लाख छियासठ हजार मात्र) आपके द्वारा पूर्व अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग के बाद ही आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा उक्त धनराशि को अपने पी०एल०ए० खाते में रखी जायेगी।
2. योजनान्तर्गत कुल राज्यांश के सापेक्ष उक्तानुसार अवशेष राज्यांश की धनराशि इस आशय से अवमुक्त की जा रही है कि इस धनराशि के विपरीत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश को शीघ्र प्राप्त कर योजना को समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या भा०स०-२२/IV-श०वि०-०८-०६(एन०य०आर०एम०)/०८ दिनांक २९-३-२००८, शासनादेश संख्या १६४६/IV(२)-श०वि०-०८-०६(एन०य०आर०एम०)/०८ दिनांक ३०-१२-२००८, शासनादेश संख्या ७३०/IV(२)-श०वि०-०९-०६(एन०य०आर०एम०)/०८ दिनांक २९-०७-२००९ एवं शासनादेश संख्या भा०स०/IV(२)-श०वि०-१०-०६(एन०य०आर०एम०)/०८ दिनांक ३१-०३-२०१० में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
5. जे०एन०एन०य०आर०एम० योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे०एन०एन०य०आर०एम० योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, २००८ एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना

नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
10. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
11. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

4— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 430/XXVII(2)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

—४८-५७

सं0 (1) / IV(2)-श0वि0-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।